उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाया धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25-11-2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1-	श्री बी0एस0 भुल्लर	प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग
2-	श्री जितेन्द्र कुमार	सचिव, माध्यमिक शिक्षा
3-	डा0 बी0एम0 जोशी	सचिव, वित्त विभाग
4-	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	सचिव, गृह विभाग
5-	श्री राकेश कुमार ओझा	सचिव, श्रम विभाग
6-	श्री ए0एन0 मिश्रा	सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग
7-	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0 निगम
8-	श्री एम0एस0ए0 सिद्दीकी	संयुक्त सचिव, प्रोटोकाल विभाग
9-	डा0 सुनील कुमार	उप सचिव, विकलॉग कल्याण विभाग

1- <u>विकलॉग कल्याण विभाग</u>

परिवहन निगम की ओर से अवगत कराया गया कि विकलॉग कल्याण विभाग पर रू0 38.26 करोड़ बकाया है। चर्चा के दौरान विकलांग कल्याण विभाग अवगत कराया गया कि अनुपूरक बजट में रू0 30.00 करोड़ का प्राविधान कराने का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था लेकिन अनुपूरक बजट में कोई प्राविधान नहीं हो सका।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा विकलांग कल्याण विभाग को यह निर्देश दिये गये कि यदि इस वित्तीय वर्ष में पुन: अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है तो परिवहन निगम की समस्त बकाया धनराशि को प्राविधान अनुपूरक बजट में कराया जाय अन्यथा अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट में सम्पूर्ण बकाया धनराशि तथा आगमी वित्तीय वर्ष में करेन्ट बिलिंग के सापेक्ष धनराशि का बजट प्राविधान कराने के लिए विकलांग कल्याण विभाग, वित्त विभाग से अनुश्रवण कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें। यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गये कि इस योजना की निरन्तरता को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन निगम के भुगतान हेतु समुचित बजट प्राविधान कराया जाय यदि बजट के अभाव में भुगतान सम्भव नहीं है तो इस योजना पर पुनर्विचार कर लिया जाए।

परिवहन निगम की बसों में विकलांग जनों की यात्रा हेतु स्मार्ट कार्ड योजना के सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि विकलांग कलयाण विभाग से समन्वय करते हुए इस सम्बन्ध में विकलांगों हेतु पोस्टपेड स्मार्ट कार्ड बनवाने की सुस्पष्ट योजना बनाकर पृथक से प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही विकलॉग कल्याण विभाग/वित्त विभाग/उ0प्र0रा0स0प0 निगम)

2- <u>गृह विभाग</u>

पुलिस विभाग पर बकाया धनराशि के भुगतान के संबंध में गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 9.00 करोड़ के भुगतान का प्रस्ताव पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था। वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त भुगतान परिवहन निगम पर बकाया यात्रीकर के विरूद्ध समायोजन करने के सम्बन्धित सूचना से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि परिवहन निगम की

http://shasanadesh.up.nic.in

यात्रीकर के मद से पूर्व वर्षो की बकाया धनराशि को माफ करने अथवा इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु परिवहन विभाग मा0 मंत्रि-परिषद के विचारार्थ अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करें। परिवहन निगम की बकाया धनराशि का नगद भुगतान, यात्रीकर से लिंक किये बिना, पुनर्विनियोग के माध्यम से किया जाए।

यह भी निर्देश दिये गये हैं कि गृह विभाग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2014 के दृष्टिगत सुरक्षा बलों के संचरण हेतु परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली बसों हेतु पर्याप्त बजट प्राविधान वर्ष 2014-15 के बजट में कराया जाए। गृह विभाग द्वारा किराये हेतु अनुमानित धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम परिवहन निगम को उपलब्ध कराया जाए तथा कुल वास्तविक किराये की अवशेष धनराशि का भुगतान प्रस्तुत बिलों के विरूद्ध किया जाए।

(कार्यवाही गृह विभाग/परिवहन विभाग/उ0प्र0रा0स0प0 निगम)

3- <u>श्रम विभाग</u>

श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2006 में आयोजित बेरोजगारी भत्ता वितरण समारोह में परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी बसों की अवशेष बकाया धनराशि रू0 1.76 करोड़ के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त धनराशि में अब तक रू0 98.00 लाख का मिलान दोनों विभागों के मध्य कराया जा चुका है जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारियों से 02 दिनों के लिये reindorse कराया जाना है तथा शेष के सम्बबन्ध में कार्यवाही गतिशील है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि रू0 98.00 लाख का शीघ्र भुगतान किया जाये तथा अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में दोनों विभाग स्तर से निस्तारण कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

(कार्यवाही श्रम विभाग/उ0प्र0रा0स0प0 निगम)

4- <u>सचिवालय प्रशासन विभाग</u>

सचिवालय प्रशासन विभाग पर परिवहन निगम की बकाया धनराशि के सम्बन्ध में चर्चा की गयी और यह पाया गया कि परिवहन निगम की भूतपूर्व मा0 मंत्रियों के मद में बकाया धनराशि गत 15 वर्षो से सम्बन्धित है। चूँकि इस अवधि में मा0 मंत्रियों का कार्यकाल समात होने के साथ-साथ इनसे सम्बन्धित निजी सचिव भी अधिकांशत: सेवानिवृत्त हो चुके है, अत: इसके दृष्टिगत इस मद में बकाया धनराशि के अपलेखन की कार्यवाही करने पर परिवहन निगम विचार कर लें। इसके साथ ही वर्तमान में उपलब्ध करायी जा रही टैक्सियों के सम्बन्ध में परिवहन निगम, सचिवालय प्रशासन विभाग से समन्वय कर एक कारगर प्रक्रिया को अपनाने की कार्यवाही करें, जिससे भुगतान समय से प्राप्त होता रहें।

(कार्यवाही सचिवालय प्रशासन विभाग/उ0प्र0रा0स0प0 निगम)

5- <u>प्रोटोकाल विभाग</u>

प्रोटोकाल विभाग पर बकाया धनराशि के संबंध में निर्देश दिए गये कि प्रोटोकाल विभाग से भुगतान के सम्बन्ध में आ रही विभिन्न कठिनाइयों के व्याख्यात्मक नोट मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया जाए जिससे परिवहन निगम को भुगतान उपलबध कराने हेतु दिशा निर्देश दिए जा सके।

(कार्यवाही प्रोटोकाल विभाग/उ0प्र0रा0स0प0 निगम)

6- <u>माध्यमिक शिक्षा विभाग</u>

परिवहन निगम द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जनपदों में सम्पन्न लैपटॉप वितरण समारोह से सम्बन्धित बिल माध्यमिक शिक्षा के जनपदीय कार्यालयों तथा

http://bhagandesh.up.nic.in

जिला प्रशासन से सत्यापित कराकर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, 18 पार्क रोड, लखनऊ को उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिनकी कुल धनराशि रू0 4.93 करोड़ है।

इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रयोजन हेतु योजना के प्रशासनिक मद से भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिसके लिये शीघ्र जनपदवार मांग/बिलों के आधार पर बजट संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है। एक सुर एक ताल समारोह की बकाया धनराशि रू0 7.15 लाख के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसके भुगतान की कार्यवाही शीघ्र करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा विभाग/उ0प्र0रा0स0प0 निगम)

इसी के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

बी0एस0 भुल्लर
प्रमुख सचिव।

संख्या:-4/1459(1)/30-2-2013, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5- प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
6- सचिव, प्रोटोकाल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ।
8- गार्ड पत्रावली।

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in